भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1635

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण

1635. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मौजूदा कृषि समुदायों को विस्थापित किए बिना आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण करने की कोई योजना है;

(ख) क्या शहरी विकास परियोजनाएं स्थानीय आबादी को आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के लिए स्थायी प्रथाओं को सुनिश्चित करेंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विस्थापित कृषि समुदायों पर शहरीकरण के प्रभाव के आकलन के लिए इस संबंध में कोई विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ऐसी नीतियां अपनाने की योजना बना रही है जो स्थिरता के लिए ग्रामीण आवासों को संरक्षित करें?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। यह राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%201(2).pdf) जारी किए हैं। यूआरडीएफआई दिशानिर्देश 2014 का अध्याय - 4 "क्षेत्रीय नियोजन दृष्टिकोण" पेरी-अर्बन क्षेत्रों की योजना से संबंधित है।

(ग) और (घ): इस मंत्रालय ने ऐसा कोई विश्लेषण नहीं किया है।

****